# ई-संदेश

04 सितम्बर, 2025 | अंक 169

## सात दिन - सात पृष्ठ

› अनावश्यक दंडात्मक प्राविधानों को समाप्त कर उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना वर्तमान की जरूरत : मुख्यमंत्री

› प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है : मुख्यमंत्री

› लोकतंत्र विश्व में शासन की सबसे अच्छी पद्धति: मुख्यमंत्री

› समाज के विभिन्न वर्गों को बिना भेदभाव मिल रहा है शासन की योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री

› केन्द्रीय रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित रेफी एम फाइबर प्रा0लि0 कम्पनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया

› टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए वरदान, टेक्नोलॉजी का उपयोग मानवता व देश हित में होना चाहिए : मुख्यमंत्री

› 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान के साथ हम सभी को जुड़ना होगा : मुख्यमंत्री

› केन्द्र व राज्य सरकार प्रत्येक विमुक्त व घुमंतू जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही : मुख्यमंत्री

› मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 02 सितम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

# अनावश्यक दंडात्मक प्राविधानों को समाप्त कर उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना वर्तमान की जरूरत : मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 28 अगस्त, 2025को यहां लखनऊ में आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में 'सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025' के प्राविधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारण्टी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'श्रमेव जयते' के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो श्रमिकों और उद्यमियों, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों।

मुख्यमंत्री जी ने विधेयक के नये प्राविधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि अनावश्यक दंडात्मक प्राविधानों को समाप्त कर, उनकी जगह पारदर्शी और न्यायसंगत व्यवस्था लागू करना वर्तमान की जरुरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि आपत्तियों और सुझावों पर गम्भीरता से विचार करते हुए विधेयक को ऐसा स्वरुप दिया जाए, जो उद्योग और श्रमिकों के हितों में संतुलन स्थापित करता हो। निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य सरकार शीघ्र ही 'सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025' लाने जा रही है। इसके अन्तर्गत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा निस्तारण अधिनियम, सिनेमा अधिनियम तथा क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा। इनमें जहाँ पहले कारावास की सज़ा का प्राविधान था, वहां अब अधिक आर्थिक दण्ड व प्रशासनिक कार्रवाई को वरीयता देने की योजना है।

प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म के मंत्र के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में औद्योगिक व श्रम सुधारों की दिशा में बड़े कदम बढ़ाए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्राविधान समाप्त करने की तैयारी की जा रही है।

बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि इस विधेयक पर सम्बन्धित 14 विभागों से राय ली गई है। अधिकांश विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई। प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेन्स की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं।

सुधारों की श्रृंखला में 'निवेश मित्र 3.0' पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके तहत निवेशकों की आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाया जाएगा। कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और ए0आई0 चैटबॉट जैसी सुविधाएँ जोड़ी जाएंगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी और निवेशकों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल का नया संस्करण शीघ्र ही लॉन्च किया जाए। इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को नई मजबूती मिलेगी।


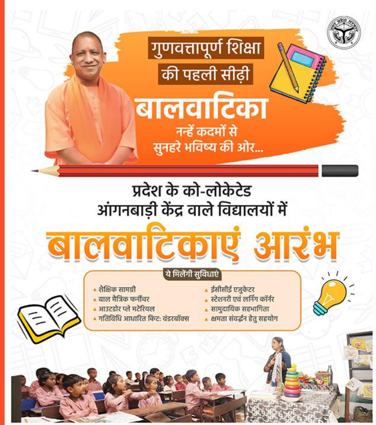

# प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 अगस्त, 2025 को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन किया और कहा कि जब मेजर ध्यानचंद जी की बात आती है, तो प्रत्येक भारतीय के मन में हॉकी की स्टिक अंकित होने लगती है। इसका कारण यह है कि मेजर ध्यानचंद ने वर्ष 1928, वर्ष 1932 और वर्ष 1936 के ओलंपिक गेम्स में हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाकर वैश्विक मंच पर भारत को एक नई पहचान प्रदान की थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में खेल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद जी की जन्मभूमि है। इसलिए प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नामकरण उनके नाम पर किया गया है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेरठ में इस सत्र से पाठ्यक्रम की शुरुआत हो गई है।

मुख्यमंत्री जी आज यहां पद्मश्री मोहम्मद शाहिद स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खेल अवसंरचना से सम्बन्धित कार्यों का लोकार्पण करने के पश्चात आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति-पत्र तथा विभिन्न राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया तथा हॉकी मैच का अवलोकन किया। उन्होंने उपस्थित युवाओं को फिट इण्डिया मूवमेण्ट की शपथ दिलायी।

उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक खिलाड़ी की तरह राष्ट्र के प्रति समर्पण, जीवन में अनुशासन, समन्वय और उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक खिलाड़ी समाज के लिए एक हीरो के रूप में होता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश व प्रदेश में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है। खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता तथा गांव-गांव में चल रही खेलकूद प्रतियोगिताएं खेल के क्षेत्र में नई क्रांति के उदाहरण हैं। देश में नई खेल नीति को लागू कर दिया गया है। अब नए खिलाड़ियों को मंच, कोचेज तथा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रदेश की प्रत्येक कमिश्नरी में एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिल सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए अलग-अलग खेलों के लिए स्पोर्ट्स कॉलेज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने, ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड व नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को कोच के रूप में नियुक्त करने का कार्य निरन्तर आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, विकास खण्ड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम निर्माण की कारवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जहां एक ओर खेल विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, वहीं प्रत्येक गांव में ओपन जिम निर्माण की कार्रवाई भी चल रही है। खेल के मैदान विकसित किए जा रहे हैं। युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यदि व्यक्ति खेल और खेलकूद की गतिविधियों से जुड़ेगा, तो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न होगा। खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ-साथ मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा। स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क के साथ प्रत्येक व्यक्ति सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएगा। इसी को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैम्पियनशिप तथा नेशनल गेम्स में प्रदेश व देश के लिए मेडल प्राप्त करने या खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को प्रत्येक वर्ष विशिष्ट अवसरों पर सम्मानित किया जाता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां अनेक अन्तरराष्ट्रीय स्तर के ओलम्पियन पैदा हुए हैं, जिसमें मेजर ध्यानचंद, के0डी0 सिंह बाबू, पद्मश्री मोहम्मद शाहिद, रवीन्द्र पाल, सैय्यद अली, डॉ0 आर0पी0 सिंह आदि सम्मिलित हैं। इसी प्रकार सुजीत कुमार, रजनीश मिश्रा, मोहम्मद शकील, देवेश चौहान, एम0पी0 सिंह, जगबीर सिंह, विवेक सिंह, राहुल सिंह, तुषार खाण्डेकर, दानिश मुर्तजा, ललित उपाध्याय, राजकुमार, प्रेम माया, रंजना श्रीवास्तव, मंजू बिष्ट, पुष्पा श्रीवास्तव, रजनी जोशी, वंदना कटारिया, रितुषा कुमारी आर्य सरीखे खिलाड़ियों ने न केवल प्रदेश, बल्कि पूरे देश को गौरवन्वित किया है। प्रदेश के खेल सचिव श्री सुहाष एल0वाई0 स्वयं भी पैरा ओलम्पिक मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदर्शन के बल पर सफलता प्राप्त करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार द्वारा विविध पुरुस्कार और सुविधालओ के अन्य लाभ भी प्रदान किये जा रहे है।

# लोकतंत्र विश्व में शासन की सबसे अच्छी पद्धति: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 अगस्त, 2025 को यहां लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज का दिन लोकतांत्रिक दृष्टि से त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता केवल मतदाता ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन भी है। जनता को सम्मान देकर उसकी आवाज को महत्व तथा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती से प्रत्येक संस्था संवेदनशील तथा विकास के प्रति आग्रही बनती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव कराने का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग के पास स्वयं का कोई भवन नहीं था। यह किराए के भवन में संचालित था। किराए के भवन में कई समस्याएं आती हैं। शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को कार्यालय भवन की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पंचायतीराज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 12 करोड़ से अधिक मतदाता ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं। देश में कई राज्यों की आबादी 12 करोड़ से अधिक नहीं है। प्रदेश में 58,000 से अधिक ग्राम पंचायत, 75,000 से अधिक क्षेत्र पंचायत के सदस्य, 826 क्षेत्र पंचायत, 07 लाख से अधिक ग्राम पंचायत के सदस्य तथा 75 जिला पंचायत हैं। प्रदेश में स्थानीय निकाय के 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद, 544 नगर पंचायत और 1,400 से अधिक पार्षद हैं, जिनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोकतंत्र आज भी विश्व में शासन की सबसे अच्छी पद्धति है।लोकतंत्र में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शासन तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर प्राप्त होता है। इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि जनता की समस्या को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जवाबदेही होती है।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से 12 करोड़ से अधिक मतदाता पंचायतीराज और लगभग 05 करोड़ मतदाता स्थानीय निकाय की व्यवस्था से जुड़ते हैं। 08 लाख से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न स्तरों पर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रक्रिया पंचायतीराज, स्थानीय निकाय व्यवस्था तथा लोकतंत्र की नींव को सुदृढ़ करती है।

मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चित समय-सीमा में कार्यदायी संस्था भवन का निर्माण कर उत्तर प्रदेश की स्थानीय निकाय और पंचायती राज व्यवस्था की कार्यप्रणाली को और बेहतर तथा सुगम बनाएगी। यह भवन आधुनिक तकनीकों से युक्त होगा। यह देश का चौथा या पांचवा राज्य होगा, जहां राज्य निर्वाचन आयोग का स्वयं का भवन होगा।

# समाज के विभिन्न वर्गों को बिना भेदभाव मिल रहा है शासन की योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 29 अगस्त, 2025 को जनपद प्रतापगढ़ में 570 करोड़ रुपये लागत की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन विकास परियोजनाओं में 263 करोड़ रुपये से अधिक की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण तथा लगभग 306 करोड़ रुपये की 70 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है।आज प्रतापगढ़वासियों को 570 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उपहार प्राप्त हो रहा है। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ का आंवला और आंवले से बने उत्पाद आज देश और दुनिया में पहुंच रहे हैं। श्री सोनेलाल पटेल के नाम पर यहां मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। प्रतापगढ़ से देश के सबसे लम्बे एक्सप्रेस-वे गंगा एक्सप्रेस-वे का लगभग 42 कि0मी0 का भाग गुजर रहा है, जो यहां के विकास को विशेष गति प्रदान करेगा। अयोध्या से प्रयागराज के मध्य बन रहा 6-लेन हाईवे जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) व मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों को आवास की प्रतीकात्मक चाभी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को रिवॉल्विंग फण्ड की धनराशि का प्रतीकात्मक चेक, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड, किसानों को ट्रैक्टर की प्रतीकात्मक चाभी तथा ओ0डी0ओ0पी0 योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत बच्चों को लैपटॉप प्रदान किए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक गांव, गरीब, महिला, नौजवान, वंचित सहित समाज के विभिन्न वर्गों को बिना भेदभाव मिल रहा है। योजनाओं का परिणाम है कि आज संतुष्टिकरण का लेवल बढ़ा है तथा सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता होने से व्यापार में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अब तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। विगत 08 वर्षों में 06 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारने में मदद मिली है।

जनपद प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की कार्ययोजना आगे बढ़ चुकी है। प्रदेश सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचन्द के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण करा रही है। इस खेल विश्वविद्यालय तक जनपद प्रतापगढ़ के युवाओं की पहुंच को आसान करने के लिए गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है। आज मेजर ध्यानचन्द की पावन जयन्ती के अवसर पर खेल विश्वविद्यालय का पहला सत्र प्रारम्भ हो चुका है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ही देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचन्द के नाम पर घोषित

किया गया। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि हर मण्डल में एक स्पोर्ट्स कॉलेज का निर्माण किया जाए। खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरन्तर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद प्रतापगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 263 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 116 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इसमें बेल्हा देवी मन्दिर के घाट का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास, लोक निर्माण विभाग की 54 परियोजनाएं, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाएं, पुलिस लाइन्स में ट्रांजिट हॉस्टल, नगर पंचायतों में कार्यालय भवन, तथा कल्याण मण्डप बनाए गए हैं। समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय चलाकपुर, राजकीय इण्टर कॉलेज दांदूपुर शिवगढ़ तथा राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज खरवई एवं बरहदा और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संग्रामगढ़ में हॉस्टल तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सण्डवां चन्द्रिका में एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन, विधानसभा पट्टी में 50 बेड का फील्ड हॉस्पिटल का निर्माण, विभिन्न थानों में पुलिस अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रतापगढ़ वासियों को विकास की सौगात को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 306 करोड़ रुपये लागत की 70 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी है। इनमें लोक निर्माण विभाग की 48 परियोजनाएं, मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय, नगर पंचायत अंतू में अग्निशमन केन्द्र, नगर पालिका परिषद बेल्हा में कल्याण मंडप, पुलिस लाइन्स में ट्रांजिट हॉस्टल, पुलिस लाइन्स में साइबर थाना, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अवस्थापना निधि के विभिन्न कार्य शामिल हैं।

# केन्द्रीय रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित रेफी एम फाइबर प्रा0लि0 कम्पनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया

भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 अगस्त, 2025 को नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में स्थित रेफी एम फाईबर प्रा0लि0 कम्पनी की रक्षा उपकरण एवं इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रेफी एम फाईबर प्रा0लि0 कम्पनी द्वारा स्थापित की गई यह इकाई देश की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई है। उन्होंने कंपनी के सी0ई0ओ0 एवं चेयरमैन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मजबूत स्वरूप अब नोएडा में भी दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में नोएडा देश की प्रगति में और अधिक सशक्त भूमिका निभाएगा। यह कम्पनी वर्ष 2017 में मात्र 10 सदस्यों से शुरु हुई थी और आज 600 से अधिक युवा इंजीनियर इसमें कार्यरत हैं। आने वाले समय में यह इकाई 5000 से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी।

रक्षा मंत्री जी ने कहा कि एक समय था, जब उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति कमजोर थी तथा कानून व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश ने नए युग की ओर कदम बढ़ाया है और आज कानून व्यवस्था की नई पहचान के साथ उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा प्रदेश बन गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश की वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देश में 02 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग केन्द्र में से एक उत्तर प्रदेश को दिया है। प्रदेश में 06 नोड में उत्तर प्रदेश डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। इसके लिए अब तक प्रदेश सरकार द्वारा 12,500 एकड़ लैण्ड अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में उपलब्ध करायी जा चुकी है। साथ ही, अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन का केन्द्र बना है। लखनऊ की जो मुस्कुराहट है, वह तब तक अधूरी थी, जब तक वहां से मिसाइल की गूंज दुश्मन के कानों तक न गूंजे। ऑपरेशन सिन्दूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के झांसी में भारत डायनामिक्स लि0 का केन्द्र भी स्थापित किया गया है। वहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। असॉल्ट राइफल ए0के0-203 का निर्माण अमेठी आयुध फैक्ट्री में किया जा रहा है। वेब्ले स्कॉट कम्पनी ने हरदोई में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है। प्रदेश व देश की सुरक्षा एवं आवश्यकता के लिए राज्य सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर आपके पास ताकत है, तो दुनिया आपके सामने नतमस्तक होगी। जब आप शक्तिशाली हैं, तो अगला व्यक्ति शांति की अपील करते हुए आपके सामने आएगा। इसीलिए कहा गया है कि 'वीर भोग्या वसुंधरा'।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत वर्ष 1947 से लगातार विभिन्न चुनौतियों का सामना करता रहा है और प्रत्येक युद्ध का पैटर्न हर एक युद्ध ने बदलते हुए देखा है। ऑपरेशन सिन्दूर ने भारत के सामर्थ्य व शक्ति का एहसास दुनिया को कराया है। हमें इस ऑपरेशन ने भविष्य की चुनौतियों से जूझने और उनका सामना करने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है।

# टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए वरदान, टेक्नोलॉजी का उपयोग मानवता व देश हित में होना चाहिए : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03 सितम्बर, 2025 को जनपद कानपुर नगर स्थित आई0आई0टी0 कानपुर में उद्योग-अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम 'समन्वय' में बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी मनुष्य के लिए वरदान है। टेक्नोलॉजी का उपयोग मानवता व देश हित में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आई0आई0टी0 कानपुर का गौरवशाली इतिहास रहा है। लगभग 06 दशकों में आई0आई0टी0 कानपुर ने देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।इस कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, साइबर सुरक्षा तथा सस्टेनिबिलिटी आदि महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित जो अलग-अलग टेक्निकल सेशन आयोजित होने जा रहे हैं उन्हें लेकर सामान्य नागरिक, समाज, देश और दुनिया संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री जी ने इण्डस्ट्री से जुड़े डेलीगेट्स व लीडर्स से कहा कि उन्हें अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा इनोवेशन, रिसर्च एण्ड डेवलपमेण्ट में उपयोग करना चाहिए। आई0आई0टी0 कानपुर भारत का पहला डीप टेक भारत-2025 विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करे। यहां डीप टेक भारत से सम्बन्धित अच्छी समिट होनी चाहिए। इस उद्देश्य से जनपद गौतम बुद्ध नगर में लैंड अलॉट की गयी है। आई0आई0टी0 कानपुर को इस क्षेत्र में लीड करना चाहिए। इस कार्य में डी0आर0डी0ओ0, इसरो और अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन्हें विगत दिनों नोएडा का ड्रोन टेक्नोलॉजी केन्द्र देखने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां हमने देखा कि हमारा युवा किस प्रकार नये भारत की सामरिक चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। आई0आई0टी0 कानपुर इन चुनौतियों का सामना करने में युवाओं को सक्षम बना रहा है। कानपुर में मेड टेक का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। अगले वर्ष यह सेण्टर प्रदेश वासियों को उपलब्ध हो जाएगा। आज प्रतिस्पर्धा के समय में हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहने का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि लोग अग्रिम पंक्ति में रहने वालों को ही याद रखते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज क्वांटम कम्प्यूटिंग के क्षेत्र में भी आई0आई0टी0 कानपुर कार्य कर रहा है। यहां विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। मैथमेटिक्स की कर्माकर थ्योरी भारत के गणितज्ञ ने दी है। गणितज्ञ कर्माकर जी को आई0आई0टी0 कानपुर के साथ जोड़ने का प्रयास चल रहा है। वह क्वांटम कम्प्यूटर से भी बेहतर कम्प्यूटर देने का सामर्थ्य रखते हैं। वह इस दिशा में यहां के विद्यार्थियों का काफी सहयोग कर सकते हैं। क्वांटम कम्प्यूटर से बेहतर कंप्यूटर बनाकर आप दुनिया को नया अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत में दुनिया के अनेक प्राचीनतम विश्वविद्यालय स्थित रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रमुख है। तक्षशिला विश्वविद्यालय ने भारत को सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्विज्ञान से जुड़े हुए विद्वान दिए थे। वहां जीवक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य ने भी अपना अध्ययन पूरा किया। जब उनके आचार्य ने उनसे वन में बिना औषधीय गुणयुक्त पौधे को खोजने के लिए कहा, तो उन्होंने वन का भ्रमण करने के पश्चात अपने गुरु से कहा कि वन में प्रत्येक पौधा औषधीय गुणों से युक्त है।यह प्रसंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि सभी मनुष्य अयोग्य हैं, वनस्पति औषधि योग्य नहीं है तथा सभी अक्षर मंत्र बनने योग्य नहीं हैं, तो यह मान कर चलिए कि कोई योजक नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, जो सभी गुणों को एक साथ योजित कर सके। आई0आई0टी0 जैसे संस्थानों की स्थापना की मंशा यही है कि वह योजक के रूप में काम करें। 'समन्वय' कार्यक्रम उस योजक के रूप में नई भूमिका का निर्वहन करेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई विज़न अवश्य होता है। मन की चेतना की तीन गतियां होती हैं। व्यक्ति के विचार चेतन अथवा अवचेतन अवस्था से उत्पन्न हो सकते हैं। मस्तिष्क का बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन मन से सम्बन्धित है। अचेतन मन के सदृश आज आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स का उपयोग किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में लगातार प्रयास हैं। किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप यहां 06 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उबर कर सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं। आज वह बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोच सकते हैं। आज हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी की चुनौती है। इस क्षेत्र में कई गम्भीर मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए गये हैं।मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े सिर्फ दो थाने थे, जिनमें एक थाना गौतम बुद्ध नगर तथा दूसरा लखनऊ में स्थापित था। दोनों ही थाने क्रियाशील नहीं थे। प्रदेश सरकार ने राज्य के समस्त जनपदों एक-एक साइबर थाने की स्थापना की। प्रदेश के 1583 थानों में साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी। इसके अतिरिक्त राज्य में स्टेट फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की गयी है। अभी इस क्षेत्र में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम लोग आई0आई0टी0 कानपुर से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं।

# 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान' के साथ हम सभी को जुड़ना होगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 03 सितम्बर, 2025 को यहां लखनऊ में लोक भवन सभागार में 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान' के अन्तर्गत प्रबुद्धजन हेतु आयोजित अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन किया । इस अवसर पर उन्होंने 'समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल' को भी लॉन्च किया। कार्यक्रम में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में विकसित भारत की संकल्पना प्रस्तुत की थी। वर्ष 2047 में यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय हमें कैसा भारत चाहिए। यह संकल्प केवल देश की सरकार का नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतवासियों का संकल्प बने, इस दृष्टि से 'विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान' के साथ हम सभी को जुड़ना है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रबुद्धजन का स्वागत करते हुए कहा कि हमारी मंशा है कि 'विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान' में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को भागीदार बना सकें। इसके लिए सभी प्रबुद्धजन का सहयोग युवाओं को जागरूक करने तथा इस अभियान को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। आप सभी रिटायर्ड प्रबुद्धजन को लोग टायर्ड न मान लें, इसलिए भी हमने आपका सहयोग लिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। आप सभी प्रबुद्धजन के पास जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों का व्यापक अनुभव है। व्यक्ति की जैसी मनोदशा होती है तथा जैसा उसका वातावरण होता है, उसके अनुरूप वह स्वयं को तैयार करता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 16वीं-17वीं सदी तक हमारा देश भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। ग्लोबल जी0डी0पी0 में भारत का योगदान 25 प्रतिशत था। 17वीं और 18वीं सदी तक आते-आते भारत का योगदान 15 प्रतिशत रह गया और चीन भारत से आगे हो गया। भारत दूसरे स्थान पर आ गया। वर्ष 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 1947 से वर्ष 1960 तक उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जी0डी0पी0 में 14 प्रतिशत योगदान था। उस समय उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। प्रदेश में सबसे उर्वरा भूमि तथा यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश देश की 08वीं अर्थव्यवस्था हो गया। राष्ट्रीय जी0डी0पी0 में इसका योगदान भी घटकर 08 प्रतिशत रह गया। इसने उत्तर प्रदेश को बीमारु बना दिया और यहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया।आज उत्तर प्रदेश बीमारु नहीं है। राष्ट्रीय जी0 डी0पी0 में प्रदेश का योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विगत 08 वर्षों में हम उत्तर प्रदेश की जी0डी0पी0 को बढ़ाने में सफल हुए हैं। प्रशासनिक टीम वही है, केवल सरकार बदली है। इस टीम ने कार्य करके दिखाया है। पहले उत्तर प्रदेश की एस0जी0डी0पी0

13 लाख करोड़ रुपये की थी, इस वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश 35 लाख करोड़ रुपये की एस0जी0डी0पी0 के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। हमने हर क्षेत्र में कार्य किया है। प्रदेश में यह सम्भावनाएं पहले भी थीं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2018 में प्रदेश में 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना की शुरुआत की गयी थी। इसके माध्यम से हमने प्रदेश के एम0एस0एम0ई0 उत्पादों की ब्रांडिंग की।

उन्हें तकनीक, मार्केट तथा डिजाइन से जोड़ने का कार्य किया। इससे हस्तशिल्पियों और कारीगरों में एक विश्वास उत्पन्न हुआ। राज्य सरकार ने इनका सहयोग किया। इसका परिणामहुआ कि उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़कर 02 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इसमें एम0एस0एम0ई0 क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें लोगों को विकसित उत्तर प्रदेश@2047 अभियान के साथ जोड़ना है। लोग उन नकारात्मक कारकों से दूर हों, जिनके कारण उत्तर प्रदेश बीमारू हुआ था। हमें विकास को लोगों के जीवन का हिस्सा बनाना है। विकास ही उनके जीवन का कायाकल्प करेगा। इसके लिए उन्हें तैयार करना होगा, जिसमें आप सभी प्रबुद्धजन का सहयोग महत्वपूर्ण है। प्रदेश विधान सभा में सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स पर लगातार 36 घण्टे तक चर्चा हुई थी। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, स्किल डेवलपमेण्ट सहित कॉमन मैन से जुड़े मुद्दे शामिल थे। इस बार सभी दलों ने सदन में विकसित उत्तर प्रदेश विषय पर लगातार 24 घण्टे की चर्चा में भाग लिया। यह चर्चा लगभग 27 घण्टे चली थी। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे, तो वह विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इस संकल्प से हर व्यक्ति को जोड़ना है।

# केन्द्र व राज्य सरकार प्रत्येक विमुक्त व घुमंतू जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 31 अगस्त, 2025 को यहां लखनऊ में विमुक्त एवं घुमंतू जातियों के कल्याणार्थ आयोजित 'विमुक्त जाति दिवस समारोह' में बतौर मुख्य अतिथि शामिल रहे। इस अवसर पर उन्होंने विमुक्त एवं घुमन्तू जातियों से जुड़े प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार प्रत्येक विमुक्त व घुमन्तू जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जनजाति समुदाय के लोगों ने अलग-अलग कालखण्डों में देश पर होने वाले हमलों का प्रतिरोध करने लिए योद्धा के रूप में काम कर अपने पराक्रम का लोहा मनवाया। परिस्थितिवश पलायन करने से घर-बार जब्त या नष्ट हो जाने के परिणामस्वरुप ये जनजातीय समुदाय घुमन्तू बन गए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सन् 1857 के प्रथम स्वातंत्र्य समर के पश्चात जब ब्रिटिश गवर्नमेन्ट को महसूस हुआ कि यह जनजातियां उन्हें लम्बे समय तक भारत पर शासन नहीं करने देंगी, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट-1871 बनाकर इन जनजातियों को प्रताड़ित किया। 31 अगस्त, 1952 को बाबा साहब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर के प्रयासों से इन जनजातियों को इस एक्ट से मुक्ति प्राप्त हुई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्त होने के पश्चात इन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विमुक्त व घुमन्तू जाति की उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रदेश के 09 जनपदों में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें रामपुर, फर्रुखाबाद, सारनाथ व चन्दापुर (वाराणसी), लखनऊ, गोरखपुर, गोण्डा, दुद्धी (सोनभद्र) तथा हसनपुर (सुल्तानपुर) स्थित विद्यालय सम्मिलित हैं। इसके अलावा ईश्वर शरण आश्रम पद्धति विद्यालय, प्रयागराज तथा प्रगति आश्रम हाईस्कूल बालागंज, लखनऊ अनुदान पर संचालित हैं। विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 101 आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं। इन सभी विद्यालयों में विमुक्त जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा इन आवासीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए भोजन, स्कूल ड्रेस, पुस्तकों आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से जनपद प्रतापगढ़ में 02 तथा जनपद लखीमपुर खीरी में 01 छात्रावास संचालित है। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावासां में भी विमुक्त जाति के छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। विमुक्त जातियों की आजीविका हेतु जनपद कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी तथा मुरादाबाद में एक ही स्थान पर निवास हेतु भूमि, कृषि योग्य भूमि का पट्टों पर आवंटन तथा विद्यालयों की स्थापना राजकीय उन्नयन बस्ती के नाम से की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा रजिस्टर्ड श्रमिकों के बच्चों तथा कोरोना कालखण्ड में अपने अभिभावकों को खोने वाले बच्चों के लिए अत्याधुनिक अवसरंचना सुविधाओं से युक्त 18 अटल

आवासीय विद्यालयां का निर्माण किया गया है। इन विद्यालयों में अब तक 18 हजार ऐसे बच्चों ने प्रवेश प्राप्त कर स्वयं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा से जोड़ा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा वनटांगिया ग्रामों को राजस्व गांव का दर्जा तथा इस समुदाय को मत देने का अधिकार दिया गया। वर्ष 2017 से पूर्व किसी भी वनटांगिया परिवार का पक्का मकान नहीं था। आज वनटांगिया समुदाय के परिवारों के लिए पक्के मकान, बच्चों के लिए स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, हॉस्पिटल आदि का निर्माण किया जा चुका है। उन्हें शासन की प्रत्येक योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। पहले मुसहर, कोल, थारु, गोंड, चेरो आदि समुदायों के लोग शासन की योजनाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से संतृप्त किया जा रहा है।

प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रजापति समुदाय के लोगों को अप्रैल से जून माह तक तालाब से निःशुल्क मिट्टी निकालने की सुविधा दी गई है। उन्हें सोलर और इलेक्ट्रिक चाक प्रदान कर मिट्टी के बर्तनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप प्रजापति समुदाय अच्छी आमदनी कमा रहा है। प्रदेश सरकार निषादों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्हें स्थानीय पट्टा उपलब्ध कराने, आवासीय योजना से जोड़ने तथा नौका प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जनपद बहराइच में भव्य स्मारक का निर्माण कराया है। जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। हाल ही में सम्पन्न उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में घुमन्तू जातियों से जुड़े युवक व युवतियां चयनित हुए हैं।

# मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 02 सितम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति में प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के नवीन उपायों तथा डिजिटल तकनीकी पर विशेष बल दिया गया है।इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को वैश्विक मान्यता प्राप्त निर्यात हब (एक्सपोर्ट हब) के रूप में स्थापित करना है।प्रदेश में निर्यातकों को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु प्रथम बार डाक घर निर्यात केन्द्र से होने वाले निर्यात, ई0सी0जी0सी0 कवरेज पर होने वाले व्यय पर अनुदान प्रदान करने के साथ-साथ परफॉरमेन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्स प्रदान किए जाने की व्यवस्था नवीन नीति में की गई है।

- मंत्रिपरिषद ने पारिवारिक सदस्यों के मध्य निष्पादित विभाजन विलेख में देय स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा 05 हजार रुपये निश्चित कर दिए जाने के प्रस्ताव को कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है। यह छूट परिवार के सदस्यों के अन्तर्गत एक विभाजन विलेख, जो अधिकतम तीन पीढ़ी के एकरेखीय वंशजों के मध्य पैतृक अचल सम्पत्ति के विभाजन से सम्बन्धित हो, पर ही, उपलब्ध होगी। यह छूट केवल उन विभाजन विलेखों पर ही उपलब्ध होगी जहाँ पारिवारिक सदस्यों के बीच पैतृक अचल सम्पत्ति का बँटवारा वर्तमान उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाले वैधानिक अंश के अनुरूप किया गया हो।

  छूट प्राप्त करने हेतु पक्षकारों को उक्त तीन पीढ़ियों का उल्लेख करते हुए विलेख में एक पारिवारिक वृक्ष/वंशावली प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसमें प्रत्येक जीवित व्यक्ति को विधि के अनुसार प्राप्त होने वाले हिस्से के मूल्यांकन को अंकित किया जाएगा। यह छूट मात्र वास्तविक व्यक्तियों के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियों के विभाजन पर उपलब्ध रहेगी। 'कल्पित व्यक्तियों' यथा फर्म, कम्पनी ट्रस्ट व संस्था आदि के स्वामित्वाधीन सम्पत्तियों पर कोई छूट उपलब्ध नहीं रहेगी।यह छूट मात्र आवासीय, व्यावसायिक एवं कृषि संपत्ति के बंटवारे पर उपलब्ध रहेगी। अन्य प्रकार की सम्पत्ति यथा औद्योगिक, संस्थागत सम्पत्ति इत्यादि की विभाजन पर यह छूट उपलब्ध नहीं रहेगी।

# मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 02 सितम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

» मंत्रिपरिषद ने कम्पनीज एक्ट-2013 के सेक्शन 8 के अन्तर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह निगम एक नियामक निकाय की भांति कार्य करेगा और अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कानूनों, नियमों एवं मानकों के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी के कार्य-कलापों/कार्य प्रक्रिया एवं कार्य-गतिविधि के कमांड एवं नियंत्रण हेतु मानकों को स्थापित करेगा।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैनपावर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, कार्मिकों को नियमों व कानूनों के अन्तर्गत स्टेट्यूटरी ड्यूज के साथ पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित कराना निगम का दायित्व होगा। निगम आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराएगा।
यह निगम आउटसोर्सिंग एजेंसियों से प्रत्येक माह की 05 तारीख को पारिश्रमिक तथा ई0पी0एफ0 व ई0एस0आई0 की धनराशि कार्मिक के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित कराएगा। कार्मिकों का ई0पी0एफ0 तथा ई0एस0आई0 खाता खुलवाएगा। कार्मिकों की कार्यक्षमता/दक्षता बढ़ाए जाने हेतु समय-समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ई0डब्ल्यू0एस0, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं इत्यादि को समय-समय पर निर्गत कानूनों/शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में आरक्षण सुनिश्चित कराएगा। आरक्षण की व्यवस्था निगम की स्थापना से नवीन आउटसोर्सिंग सेवाओं पर लागू होगी, पूर्व की सेवाओं/मैनपावर पर नहीं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम (यू0पी0सी0ओ0एस0) के गठन एवं जेम निविदा के माध्यम से चयनित नयी आउटसोर्सिंग एजेंसी के उपरान्त भी वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कार्मिकों की सेवाएं ली जाएंगी तथा उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी।

» मंत्रिपरिषद ने जनपद कानपुर तथा लखनऊ एवं उसके समीपवर्ती महत्वपूर्ण कस्बों में नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (NCC) मॉडल पर ई-बसों को संचालित कराए जाने सम्बन्धी आर0एफ0पी0 अभिलेख और ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंट को अनुमोदित किया है। मंत्रिपरिषद ने परियोजना प्रस्ताव की अन्तर्वस्तु में संशोधन/परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होने पर पी0पी0पी0 बिड इवैल्यूएशन कमेटी की संस्तुति के आधार पर आर0एफ0पी0 अभिलेख और ड्राफ्ट कन्सेशन एग्रीमेंट में आवश्यक सुसंगत संशोधन हेतु नगर विकास मंत्री को अधिकृत किया है।

# मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 02 सितम्बर, 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

- मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति-2025' (UP ECMP-2025) को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह नीति 01 अप्रैल, 2025 से 06 वर्षों के लिए वैध होगी तथा इसका क्रियान्वयन शासन स्तर पर गठित नीति कार्यान्वयन इकाई सशक्त समिति की देखरेख में नोडल संस्था द्वारा किया जायेगा।

- मंत्रिपरिषद ने समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की शर्तों के अनुसार 'स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्थापना' किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिपरिषद द्वारा उक्त समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) की शर्तों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर तद्नुसार अपेक्षित परिवर्तन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है

- मंत्रिपरिषद ने जनपद वाराणसी, तहसील-सदर के अन्तर्गत मौजा व परगना रामनगर में स्थित आराजी नं 0-507 एवं 508 की 03 एकड़ भूमि पर समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सी0आर0सी0) की स्थापना हेतु उक्त भूमि दिव्यांगजन सशक्तिरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार (डी0ई0पी0 डब्ल्यू0डी0) को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए निदेशक श्री विशाल सिंह, आईएएस द्वारा प्रकाशित